नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
(NATIONAL EDUCATION POLICY - 1986)

भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं में बेशकीमती संपदा है. आवश्यकता केवल बात की है कि उसका पालन-पोषण गतिशील एवं संवेदनशील हो. प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है. जन्म से मृत्यु तक जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसकी अपनी आवश्यकता एवं समस्या होती है. विकास की इस गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा ही मनुष्य की सभी ताकत हो सकती है।

आजाद भारत में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई आयोग बने। परन्तु सरकार के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा नीतियां एवं कार्यक्रम भी परिवर्तित होते रहे। शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, परन्तु 1977 में भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही जनता दल की सरकार बनी। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्र ने 1979 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। परन्तु जनता दल की सरकार गिरने के साथ ही कांग्रेस की सरकार ने 1968 शिक्षा नीति को रद्द किया। इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का नाम दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुल 12 अध्याय

Importance of National education Policy

(i) प्रस्तावना (Introduction) (भूमिका)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रस्तावना में यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के कारण 10+2+3 शिक्षा संरचना को स्वीकार कर लिया गया है। यह शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में विज्ञान तथा गणित विषय को अनिवार्य बना दिया है। देश की जनसंख्या वृद्धि को कम करने का प्रयास स्त्रियों में साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि करके ही करना होगा।

(ii) शिक्षा की भूमिका (Role of Education)

(a) हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है।

(b) शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी सहायता करती है।

(c) शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है।

(d) शिक्षा मनुष्य को विचारशील, राष्ट्रप्रेमी सभ्य, सुसंस्कृत उत्तम नागरिक बनाती है अतः राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National system of Education)

(a) राष्ट्रीय शिक्षा ~~व्यवस्था~~ (प्रणाली) का मूलमंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जाति-पाति, धर्म, स्थान, लिंग के बिना भेदभाव के एक जैसी शिक्षा उपलब्ध हो। ~~सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ।~~

(b) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर पर प्रत्येक बच्चे की शिक्षा हेतु सामान्य शिक्षा प्रणाली (Common school system) को अपनाने हेतु प्रभावशाली कदम उठाया जाए।

(c) राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यह जरूरी है कि देश में एक ही प्रकार की शिक्षा संरचना हो। 10+2+3 की संरचना पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है, उसका विभाजन इस प्रकार हो कि प्राथमिक स्तर 5 वर्ष की, उच्च प्राथमिक 3 वर्ष की तथा 2 वर्ष का हाई स्कूल हो।

(i) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुछ
(i) UGC
(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Reasearch)
(iii) अखिल भारतीय तकनीक परिषद (Indian Council of technical education)
(iv) भारतीय चिकित्सा परिषद (Indian medical Council)
(v) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of educational Research and training. NCERT)
(vi) अन्तराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान (National institute of educational planing and Administration)

(vii) समानता के लिए शिक्षा (education for equality)

⇒ नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने के लिए पर विशेष बल देगी, क्योंकि महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा विकलांगों की शिक्षा में पर्याप्त असमानताएं थी।

(a) महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा (education for Women's equality)

⇒ शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा

→ महिलाओं में शिक्षा का प्रसार किया जाए एवं बालिकाओं उसके को भी शिक्षा से वंचित रह जाती है, उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाए।

(b) अनुसूचित जातियों की शिक्षा (Education for Scheduled Cast)

→ गरीब जन जातियों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए की 14 वर्ष की उम्र तक नियमित स्कूल आ सके।

→ जो बच्चे 10th के पहले कल कारखाना उद्योग या अन्य किसी भी तरह के कार्य करते है उन्हे छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जाए

→ अनुसूचित जातियों के लिए के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए

→ प्रत्येक जिला में छात्रावास हो जाए

(c) विकलांग की शिक्षा (Education for Handicapped)

→ दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेद-भाव कानूनन अपराध माना जाएगा।

→ गंभीर रूप से विकलांग बच्चो के लिए छात्रावास वाले विद्यालयों की व्यवस्था की जाए।

→ दिव्यांग बच्चे समान्य बच्चो के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते है

→ प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक नामांकन में आरक्षण किया जाए।

→ शिक्षकों की नियुक्ति में, दिव्यांग छात्रों को विशेष छूट मिले।

(5) शिक्षा का पुनर्गठन (Reorganization of education)

(a) शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा (Early Childhood Care and education)

→ प्रत्येक विद्यालय में शिशुओं के देखभाल का केन्द्र खोला जाए

→ play school में बच्चों की शिक्षा पूरी तरह बाल केन्द्रित होनी चाहिए

→ इस कार्य के लिए स्थानीय समुदाय की सहायता लिया जाए

(b) प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary education)

→ 14 वर्ष तक बच्चों नामांकन एवं नियमित शिक्षा दिया जाए एवं तय किया जाए कि बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़ें

→ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।

→ किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड न दिया जाए।

→ operation Blackboard के अन्तर्गत विद्यालय में दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शा, चार्ट, मॉडल, कम से कम दो शिक्षक की व्यवस्था की जाए।

→ teaching method बालकेन्द्रित होना चाहिए

→ बच्चों की जीवन अनुसार time-table एवं अवकाश निर्धारित किया जाए।

(3) माध्यमिक शिक्षा (Secondary education)

→ माध्यमिक शिक्षा की संरचना 10+2 द्वारा देश का आर्थिक विकास पर बल दिया जाए

→ 10+2 की शिक्षा में 1990 तक 10% बच्चों को एवं 1995 तक 25% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए

→ बदलते वक्त के साथ teaching method पर बदलाव किया जाए

→ स्त्रियां, ग्रामीण, जनजातियों एवं अल्पसंख्यक बच्चों की व्यावसायिक संबंधी आवश्यकता को सरकार दूर करेगी।

(4) उच्च शिक्षा (higher education)

→ शिक्षा के स्तर को जांच करने की जिम्मा UGC को दिया जाए

→ देश की जरूरत को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को नये सिरे से तैयार किया जाए

→ शिक्षण-विधि में भी बदलने का प्रयास किया जाए

→ अपनी संस्कृति को ~~बचाने~~ बचाने के लिए प्रादेशिक भाषा पर बल दिया जाए

→ open university की शुरुआत किया जाए
→ IGNOU का विस्तार पूरे देश में किया जाए (1985)
→ शहरी विश्वविद्यालय की तरह ग्रामीण विश्वविद्यालय भी सुविधा दिए जाए

⑥ तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical & management education)

→ (1) अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे तथा सेवा क्षेत्र और शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, ग्रामीण रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकि की आवश्यकता है, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा

(2) जनशक्ति की सूचना प्रणाली को विकसित किया जाए

(3) Computer शिक्षा को स्कूल स्तर से शुरु किया जाए

(4) महिलाएँ, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं विकलांग के लिए तकनीक की माध्यम से औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया जाए

(5) तकनीक को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाए

(6) पुराने पाठ्यक्रम को हटाकर तकनीक आधारित विषय तैयार किया जाए

NOTES

(7) शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन (Implement of education system)

(1) शिक्षकों का स्वायत्ता प्रदान सुविधा दी जाए परन्तु जवाबदेही भी तय हो

(2) छात्रों की रायशुमारी पर काम किया जाए

(3) ~~शिक्षक~~ शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक एवं आर्थिक सुविधा दिया जाए

(4) शिक्षा के सभी कार्य को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development)

(8) आधुनिक शिक्षा का विषय-वस्तु (Content of modern education)

(1) पर्यावरण के प्रति जागरूकता विद्यालय एवं कॉलेज की शिक्षा का अंग होगा।

(2) खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अंग माना जाएगा।

(3) त्रिभाषा सूत्र को और मजबूत किया जाए

(4) स्कूल व कॉलेज तक Marksheet पर grade दिया जाए

(5) मूल्यांकन कार्य शिक्षक, छात्र एवं माता-पिता तीनों मिल कर करें

(6) कॉलेज शिक्षा तक sem सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाए।

(7) Exam के दौरान अध्यापकों में सुधार किया जाए ताकि किसी छात्र के साथ अन्याय न हो।

(8)

(9) अध्यापक (Teacher)

(1) शिक्षकों के चयन में उनकी प्रतिभा को आधार माना जाए
(2) शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण-पद्धति की framing किया जाए
(3) NCERT के शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सुविधा मिले।
(4) शिक्षकों की जवाबदेही के मानक तैयार किया जाए

10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

(10) शिक्षा का प्रबंध (Management of education)

(a) राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) का किया जाए

(b) महिलाओं को अयाधा ...... शामिल करना का उद्देश्य होना चाहिए

(c) केन्द्र तथा राज्य के शिक्षा विभागों को मजबूत करने के लिए व्यावसायिक क्षमता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए

(d) सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षक संस्थाओं को संचालन के लिए अयाधा/उपयोग प्रशिक्षण दिया जाए

(e) शिक्षा को व्यवसाय (पैसा कमाने का तरीका) न समझा जाए, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।

(f) और गैर सरकारी शिक्षा संस्थाएँ शिक्षा ...... हित में हो उचित विलय सहायता दी जाए।

(g) शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यकता को देखते हुए जिसमें देश का विकास एवं जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो तैयार किया जाना चाहिए।

① संसाधन तथा समीक्षा
(Resources and Review)

(a) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा के उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है. अतः शिक्षा में इसी निवेश को

(b) शिक्षा के लिए जहाँ तक सम्भव हो गैर-सरकारी तरीके से साधन जुटाने के लिए, यहाँ इच्छुक दाता, कॉर्पोरेट सेक्टर तथा N.G.O, उच्च शिक्षा में छात्रों से फीस तथा स्थानीय लोगों से चंदा लेना होगा, आदि पर कार्य सरकार तथा देशवासियों के सहयोग से होगा।

(c) शिक्षा में इसी निवेश प्रत्येक साल बढ़ाया जाए

(d) राष्ट्रीय कुल आय का 6% तक खर्च शिक्षा में हो

(e) प्रत्येक पाँच साल में शिक्षा में कुल खर्च की समीक्षा की जाए

NOTES

22 2013
Monday
April

112-253 • WK 17

wk	M	T	W	T	F	S	S
09					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

April 2013

wk	M	T	W	T	F	S	S
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30					

(12) भावी स्वरूप (The ~~futhe~~ future structure)

9:00
10:00
राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक 10 साल में बननी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप समय एवं आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। नई शिक्षा नीति विदेशी शासन द्वारा देश में उत्पन्न विषमताओं को दूर करके एवं राष्ट्र का विकास किया जाना चाहिए, नई शिक्षा नीति में 100% साक्षरता का हमारा लक्ष्य होगा।

11:00
12:00
1:00
2:00